झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
एल.पी.ए संख्या 592/2022
के साथ
अंतरवर्ती आवेदन संख्या 10971/2022

---

1. झारखंड राज्य।

2. प्रमुख सचिव, शहरी विकास एवं आवास विभाग, झारखंड सरकार का कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा,डाक घर . थाना धुर्वा जिला रांची

3. अपर सचिव-सह-पूछताछ अधिकारी, शहरी विकास और आवास विभाग, झारखंड सरकार का कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाक घर और थाना धुर्वा, जिला-रांची में है।

…. …. अपीलकर्ता

बनाम

1. वेद प्रकाश सिंह उम्र लगभग 49 वर्ष, पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह, निवासी क्वाटर नंबर बी/II-398 (टी),
डाक घर . और थाना धुर्वा, जिला रांची (झारखंड)।

… … उत्तरदाता/याचिकाकर्ता

2. श्री अभिषेक कुमार, पिता स्वर्गीय नरसिंह प्रसाद, निवासी क्वाटर नंबर डीटी-1/03, डैम साइड, धुर्वा,
डाकघर एवं थाना .धुर्वा, जनपद-रांची।

3. राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड का कार्यालय निर्वाचन भवन, न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, रांची, डाकघर जीपीओ थाना रातू रोड, जिला रांची में है।

…. …. प्रोफार्मा उत्तरदाता

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

अपीलकर्ताओं के लिए : श्रीमती वंदना सिंह, अधिवक्ता रेस

उत्तरदाता नंबर 3 के लिए : श्री सुमित गडोदिया, एडवोकेट
श्रीमती शिल्पी गडोदिया, एडवोकेट

आदेश संख्या.26/दिनांक 16 अप्रैल, 2024

न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, के अनुसार

1. इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 5616/2021 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 27.07.2022 जिसके द्वारा रिट याचिका की अनुमति दी गई है, के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट के खंड (क्लाज)10 के तहत यह तत्काल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गयी है

. अंतरवर्ती आवेदन संख्या **10971/2022**

2.तत्काल अपील को सीमा द्वारा प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि दिनांक 22.12.2022 के कार्यालय नोट के अनुसार, अपील को प्राथमिकता देने में 110 दिनों की देरी है, इसलिए, इस तरह की देरी को माफ करने के लिए अंतरवर्ती आवेदन संख्या 10971/2022 आवेदन दायर किया गया है।

3.इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 110 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की गई है, यह उचित और उचित समझता है, योग्यता के आधार पर आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य पर जाने से पहले देरी माफी आवेदन पर विचार करने के लिए।

4. आवेदक-अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अपील को प्राथमिकता देने में देरी को उसमें दिखाए गए आधारों के आधार

पर अंतरवर्ती आवेदन की अनुमति देकर इसे पर्याप्त मानते हुए माफ किया जा सकता है।

5. अपील को प्राथमिकता देने में देरी को माफ करने का आधार, जैसा कि अंतरवर्ती आवेदन में उल्लेख किया गया है, यह है कि दिनांक 27.07.2022 के आदेश के डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5616 में पारित होने के बाद

WP (सी) संख्या 5616/2021 में पारित होने के बाद 22.08.2022 को झारखंड सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के अवर सचिव के समक्ष फाइल रखी गई थी।

इसके बाद, फाइल को 07.09.2022 को अतिरिक्त सचिव के समक्ष रखा गया ताकि फाइल को एल.पी.ए. दाखिल करने के निर्देश के लिए विभाग के सचिव के समक्ष रखा जा सके और विद्वान महाधिवक्ता से राय भी ली जा सके।

इसके बाद, अतिरिक्त सचिव डब्ल्यूपी (सी) संख्या 5616/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 के खिलाफ एलपीए दायर करने के लिए झारखंड सरकार के विधि विभाग की राय लेने के लिए 08.09.2022 को झारखंड सरकार के शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव के समक्ष फाइल रखी गई।

इसके बाद, एल.पी.ए दाखिल करने के लिए राय लेने के लिए फाइल को 09.09.2022 को झारखंड सरकार के कानून और न्याय विभाग के समक्ष रखा गया था।

इसके बाद, दिनांक 27.07.2022 के आदेश के खिलाफ एल.पी.ए दाखिल करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता की राय के बाद, आधार तैयार करने के लिए फाइल 20.09.2022 को विद्वान एएजी-II के कार्यालय में भेजी गई और कुछ और दस्तावेजों की आवश्यकता थी

एल.पी.ए तैयार करने के लिए और इस बीच दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हो गईं और विभाग को भी बंद कर दिया गया, इसके बाद विभाग द्वारा एएजी-II के कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध कराए गए।

तत्पश्चात्, विलंब की क्षमा के लिए तत्काल अन्तर्वर्ती आवेदन के साथ एल.पी.ए दायर किया गया है।

6. हमने देरी से माफी आवेदन पर अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील को सुना है और उस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्तावों को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अत्यधिक देरी को माफ करने में न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में प्रतिपादित किया गया है।

7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर *लिस*(मुकदमा) को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना है, लेकिन निश्चित रूप से यदि अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह वाद की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार *करे*।

8. यह यहां उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सीमा का कानून कानूनी *कहावत इंटरेस्ट रीपब्लिके यूटी सिट फिनिस लिटियम* में निहित है

(यह सामान्य कल्याण के लिए है कि एक अवधि को मुकदमेबाजी में रखा जाए)। सीमा के नियम पक्षकारो के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं

9. पक्षकारों, बल्कि विचार यह है कि प्रत्येक कानूनी उपाय को विधायी रूप से निश्चित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि बृजेश ***कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, (2014) 11 एससीसी 351 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आयोजित किया गया है।***

10. जनरल एक्सीडेंट फायर एंड लाइफ एश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम जन्महोमेद अब्दुल रहीम, (1939-40) 67 आईए 416 ***में प्रिवी काउंसिल ने*** टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा किया, जिसमें यह कहा गया है कि:

11. *"सीमा और सुखाधिकार पाने का एक कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से संचालित हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा प्रदान करता है, तो इसे किसी विशेष पार्टी के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधार पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित कर सकता है, या कानून द्वारा मान्यता प्राप्त अपवादों का परिचय दें।*

12. पीके रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एससीसी 556 ***में***, सर्वोच्च न्यायालय ने 565 दिनों की देरी की माफी के मामले पर विचार करते हुए, जिसमें देरी की माफी के लिए कोई स्पष्टीकरण बहुत कम उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, पैराग्राफ -6 में निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

13. *"6. परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है और न्यायालयों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है।*

14. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, ईशा ***भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी, (2013) 12 एससीसी 649 में यह न्यायालय***,

निम्नानुसार आयोजित: किया है ;

> *"21.5 (v) देरी की माफी मांगने वाले पक्ष के लिए आरोपित सदाशयता का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।*
>
> *21.7. (vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना है और इसे पूरी तरह से निरंकुश मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।*
>
> *21.9. (ix) किसी पार्टी का आचरण, व्यवहार और उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित रवैया प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उदार दृष्टिकोण के नाम पर उक्त सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।*
>
> *22.4. (डी) देरी को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में देखने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को एक बेपरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।*

15. कानून की यह स्थापित स्थिति है कि जब कोई वादी सदाशयी उद्देश्य से कार्य नहीं करता है और साथ ही, निष्क्रियता और अपनी ओर से कमी के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि

समाप्त हो जाती है, तो ऐसी सदाशयता की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिन्हें विलंब की माफी के प्रश्न पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संबंध में गुजरात राज्य द्वारा सचिव एवं अन्य बनाम ***कनुभाई कांतिलाल राणा, 2013 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 4202***,और अन्य के माध्यम से गुजरात राज्य में गुजरात उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता ***है।*** जिसमें, पैराग्राफ -17 में, यह माना गया है कि "कानून ने 30 दिन की सीमा की एक निश्चित अवधि निर्धारित की है, अपील दायर करने के दिनों के लिए''.

सरकार सीमा की अवधि के प्रावधानों की अनदेखी नहीं कर सकती क्योंकि यह विधायिका का इरादा कभी नहीं था कि जब सरकार अपीलकर्ता है तो सीमा की एक अलग अवधि होनी चाहिए।

पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और अन्य, [(2012) 3 एससीसी ***563] के मामले में,*** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 27 से 29 पर निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> *"**27.** यह विवाद में नहीं है कि संबंधित व्यक्ति इस न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने के माध्यम से मामले को लेने के लिए सीमा की निर्धारित अवधि सहित शामिल मुद्दों से अच्छी तरह से अवगत या परिचित थे। वे यह दावा*

नहीं कर सकते कि उनके पास सीमा की एक अलग अवधि है जब विभाग के पास अदालत की कार्यवाही से परिचित सक्षम व्यक्ति थे। प्रशंसनीय और स्वीकार्य स्पष्टीकरण के अभाव में, हम यह प्रश्न उठा रहे हैं कि विलंब को यांत्रिक रूप से केवल इसलिए माफ क्यों किया जाना चाहिए क्योंकि सरकार या सरकार का एक स्कंध हमारे समक्ष एक पक्ष है।

28. *यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि विलंब की माफी के मामले में जब कोई घोर लापरवाही या जानबूझकर निष्क्रियता या सदाशयता की कमी नहीं थी, पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाने के लिए एक उदार रियायत को अपनाया जाना चाहिए, हमारा विचार है कि तथ्यों और परिस्थितियों में, विभाग पहले के विभिन्न निर्णयों का लाभ नहीं उठा सकता है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों के उपयोग और उपलब्ध होने के मद्देनजर अवैयक्तिक मशीनरी और विरासत में मिली नौकरशाही पद्धति के कारण कई नोट बनाने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। परिसीमा का कानून निस्संदेह सरकार सहित सभी को बाध्य करता है।*

29. *हमारे विचार में, सभी सरकारी निकायों, उनकी एजेंसियों और संस्थाओं को यह सूचित करने का सही समय है कि जब तक उनके पास देरी के लिए उचित और स्वीकार्य स्पष्टीकरण नहीं है और वास्तविक प्रयास नहीं किए गए हैं, तब तक सामान्य स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है कि फाइल को -कई महीनों/वर्षों तक लंबित रखा गया था।*

प्रक्रिया में प्रक्रियात्मक लाल टेप। सरकारी विभागों पर यह सुनिश्चित करने का विशेष दायित्व है कि वे अपने कर्तव्यों का पालन परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ करें। देरी की माफी एक अपवाद है और इसे सरकारी विभागों के लिए प्रत्याशित लाभ के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कानून सभी को एक ही रोशनी में आश्रय देता है और कुछ लोगों के लाभ के लिए इसे घुमाया नहीं जाना चाहिए।

इसी तरह, मध्य प्रदेश राज्य ***और अन्य बनाम चैतराम मेवाडे,*** *[**(2020) 10 एससीसी 667**]*,में माननीय सर्वोच्च न्यायालय पोस्ट मास्टर जनरल और अन्य बनाम ***लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड और एन.आर.*** (सुप्रा,) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का उल्लेख करने के बाद पैराग्राफ 1 से 5 में निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

*"**1.** मध्य प्रदेश राज्य बार-बार एक ही काम करता रहता है और आचरण असुधार्य प्रतीत होता है। विशेष अनुमति याचिका 588 दिनों की देरी के बाद दायर की गई है। हमें मध्य प्रदेश राज्य द्वारा राज्य में अपील दायर करने में इस प्रकार की असाधारण देरी से निपटने का अवसर मिला था*

म.प्र.[राज्य]बनाम भेरूलाल

एम.पी. भेरूलाल, (2020) 10 एससीसी 654] हमारे आदेश दिनांक 15-10-2020 के संदर्भ में।

2. हमने उस मामले में एक विस्तृत आदेश दिया है और हमें उसी तर्क को फिर से दोहराने का कोई उद्देश्य नहीं दिखता है, सिवाय उन तथ्यों को रिकॉर्ड करने के जो उन तथ्यों को दर्ज करते हैं जिन पर देरी को माफ करने की मांग की गई है। 5-1-2019 को, यह कहा गया है कि 13-11-2018 [चैतराम मेवाडे बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2018 एससीसी ऑनलाइन एचपी 1632] को दिए गए निर्णय के संबंध में सरकारी वकील से संपर्क किया गया था और कानून विभाग ने 26-5-2020 को आक्षेपित आदेश के खिलाफ एसएलपी दायर करने की

अनुमति दी थी। इस तरह विधि विभाग ने यह फैसला करने में करीब 17 महीने का समय लिया कि एसएलपी दायर की जानी है या नहीं। विधि विभाग के लिए अक्षमता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र क्या होगा।

3. हम मध्य प्रदेश राज्य के मुख्य सचिव को विधि विभाग के पुनर्गठन के पहलू पर गौर करने का निर्देश देना उचित समझते हैं क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि विभाग किसी भी उचित अवधि के भीतर अपील दायर करने में असमर्थ है, बहुत कम समय सीमा के भीतर। इस तरह के बहाने, जैसे

> *पूर्वोक्त आदेश में पहले से ही दर्ज किए गए पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड [पोस्टमास्टर जनरल बनाम लिविंग मीडिया (इंडिया) लिमिटेड, (2012) 3 एससीसी 563: (2012) 2 एससीसी (सीआईवी) 327 में निर्णय के मद्देनजर स्वीकार्य नहीं हैं:*
>
> *(2012) 2 एससीसी (सीआरआई) 580: (2012) 1 एससीसी (एल एंड एस) 649]*

4. हमने अपनी चिंता भी व्यक्त की है कि इस प्रकार के मामले केवल "प्रमाण पत्र मामले" हैं ताकि इस मुद्दे को शांत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्तगी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सके। उद्देश्य उन अधिकारियों की त्वचा को बचाने के लिए है जो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं। हमने उस स्थिति की विडंबना को भी दर्ज किया है जहां उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है जो इन फाइलों को दबाकर रखते हैं और कुछ नहीं करते हैं।

5. देरी की अवधि और जिस आकस्मिक तरीके से आवेदन को लिखा गया है, उसमें शामिल न्यायिक समय की बर्बादी को देखते हुए, हम याचिकाकर्ता राज्य पर मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के साथ जमा करने के लिए 35,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। यह राशि चार सप्ताह के भीतर जमा की जाए। दाखिल करने में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी (अधिकारियों) से राशि वसूल की जाए और फाइलों पर बैठा दिया जाए और उक्त राशि की वसूली का प्रमाण पत्र भी उक्त अवधि के भीतर इस न्यायालय में दायर किया जाए। हमने डिप्टी एडवोकेट जनरल को चेतावनी दी है कि इस तरह के किसी भी क्रमिक मामलों के लिए लागत बढ़ती रहेगी।

रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एससीआर 762 ***में माननीय सर्वोच्च न्यायालय***

ने माना है कि केवल इसलिए कि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बताए गए हैं, अपीलकर्ता को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> *"**12.** तथापि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में विलंब की माफी का हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का प्रमाण धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए; विलंब को क्षमा करने के आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो अदालत को जांच करनी होगी कि क्या*
>
> *इसका विवेकाधिकार यह देरी को माफ करना चाहिए। मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पार्टी या उसकी सदाशयता का परिश्रम विचार के लिए गिर सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मान सकता है। यह इस जांच को सही नहीं ठहरा सकती कि पार्टी अपने पास उपलब्ध हर समय निष्क्रिय क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो सदाशयता या उचित परिश्रम के विचार हमेशा भौतिक और प्रासंगिक होते हैं। ऐसे आवेदनों से निपटने में न्यायालय को धारा 5 और*
>
> *14. इसलिए, हमारी राय में, जिन विचारों को धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से भौतिक और प्रासंगिक बनाया गया है, उन्हें उसी हद तक और उसी तरीके से उन आवेदनों से निपटने में लागू नहीं किया जा सकता है जो धारा 5 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के तहत तय किए जाते हैं"*

14. वर्तमान मामले में यह धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है कि अपीलकर्ता के पक्ष में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि परिसीमा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता के परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य नहीं दिया गया था। वास्तव में, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, विद्वान न्यायिक आयुक्त ने अपीलकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर देरी के लिए माफी के लिए खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके अपील दायर करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था, और हमारी राय में, यह एक वैध आधार नहीं है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलंब माफी आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को विलंब की माफी के लिए पर्याप्त कारण पर विचार करने की आवश्यकता होती है और वादी के दृष्टिकोण पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या यह *सदाशयी है* या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित होता है और इस तरह, वादी के वास्तविक उद्देश्य पर गौर करना आवश्यक है और साथ ही, निष्क्रियता और उसकी ओर से कमी के कारण।

इसमें यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार ***बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एससीसी 81]*** **में किया गया है,** जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 से 15 में आयोजित किया गया है: -

*"**9.** पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, जितना कि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, शब्द "पर्याप्त" उस से अधिक नहीं गले लगाता है जो एक प्लैटिट्यूड (तुच्छता) प्रदान करता है, जो जब किया गया कार्य किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, तो एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से विधिवत जांच की जाती है। इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "लगन से काम नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संबंधित अदालत को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को यह जांचना होगा कि क्या गलती वास्तविक है या केवल एक गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था। (देखें मणींद्र भूमि और बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [एआईआर 1964 एससी 1336], माता दीन बनाम ए नारायणन [(1969) 2 एससीसी 770: एआईआर 1970 एससी 1953]*

, परिमल बनाम वीणा [(2011) 3 एससीसी 545: (2011) 2

(क) क्या यह सच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एससीसी (सीआईवी) 1 एआईआर 2011 एससी 1150 और मणिबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम लिमिटेड (सिवि) के मामले में दिनांक 10-11-2010 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में

दिनांक 10-11-2010 के आदेश के माध्यम से दिनांक 1 (2012) 5 एससीसी 157 : (2012) 3 एससीसी (सीआईवी) 24
एआईआर 2012 एससी 1629] .)

16. *अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्रा कुमार [एआईआर 1964 एससी 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर को समझाया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक*

> *अच्छा कारण और इसके विपरीत। हालांकि, यदि कोई अंतर मौजूद है, तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का अनुपालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाता है।*

17. अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पार्टी पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई (*स्ट्रेटजैकेट*) सीधा साधा फार्मूला संभव *नहीं है (मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 2एससीसी 535: एआईआर 2002 एससी 100] और राम नाथ साव बनाम गोबर्धन साव [(2002) 3 एससीसी 195: एआईआर 2002 एससी 1201] के माध्यम से।*

18. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। "एक वैधानिक प्रावधान से बहने वाला परिणाम कभी भी एक बुराई नहीं है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न संकट मानता है। वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूर्ण प्रभाव देते हुए इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी कहावत ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि, "असुविधा एक निर्णायक कारक नहीं है" जिस पर एक क़ानून की व्याख्या करते समय विचार किया जाना चाहिए।

19. सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर स्थापित किया गया है, इसका उद्देश्य समुदाय में शांति को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय बीतने के बाद से बासी हो गए हैं। इंग्लैंड के हाल्सबरी के नियमों के अनुसार, वॉल्यूम 28,P 266/...

> *"605. परिसीमा अधिनियमों की नीति- न्यायालयों ने सीमाओं की विधियों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात्, (1) कि लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक है, (2) कि एक प्रतिवादी ने एक बासी दावे का खंडन करने के लिए सबूत खो दिया है, और (3) कार्यों के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।*
>
> *एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा इक्विटी और न्याय में हासिल की गई गड़बड़ी या वंचित होने से रोकती है*
>
> *लंबे समय तक आनंद से या किसी पार्टी की अपनी निष्क्रियता, लापरवाही या लापरवाही से क्या खो सकता है। (देखें पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन [(2005) 7 एससीसी 510] , राजेंद्र सिंह बनाम संता सिंह [(1973) 2 एससीसी 705: एआईआर 1973 एससी 2537]*
> *और पुंडलिक जालम पाटिल बनाम जलगांव मध्यम परियोजना [(2008) 17 एससीसी 448]*

20. पी. रामचंद्र राव बनाम कर्नाटक राज्य (2002) 4 एस.सी.सी.578 में इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को लागू करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक [(1992) 1 एससीसी 225] में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के सामने उड़ जाएगा।

21. इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां एक मामला सीमा से परे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत

से संपर्क करने से रोका। यदि कोई पक्ष लापरवाह पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से सदाशयता की कमी के कारण, या यह पाया जाता है कि उसने लगन से काम नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत द्वारा कोई भी शर्त लगाकर इस तरह के असाधारण विलंब को माफ करने का कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर विलंब की क्षमा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के देरी को माफ करने के लिए समय पर अदालत जाने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त लगाना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करने के समान है और यह विधायिका की अवहेलना दिखाने के समान है।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर कार्य नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संबंधित न्यायालय को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी

न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, इसका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना होता है। आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को यह जांचना

होगा कि क्या गलती सदाशयी है या केवल गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था जैसा कि ***मनिंद्रा लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य, एआईआर 1964 एससी 1336, लाला मातादीन बनाम ए नारायणन, (1969) 2 एससीसी 770, परिमल*** *बनाम* ***वीणा*** उर्फ़ ***भारती, (2011) 3 एससीसी 545 में आयोजित किया गया है।***

और मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157।

पूर्वोक्त निर्णयों में आगे यह माना गया है कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पक्ष पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई सीधा साधा(स्ट्रेटजैकेट) फॉर्मूला संभव नहीं है, इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है

राम नाथ साव उर्फ़ राम नाथ साहू और अन्य बनाम गोबर्धन साव और अन्य, (2002) 3 एससीसी 195 ***में न्यायालय***, जिसमें, पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

*"**12.** इस प्रकार, यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम*

की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी अन्य समान प्रावधान के अर्थ के भीतर अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" को एक उदार निर्माण प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की कमी किसी पार्टी के लिए आरोपित न हो। किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कदम उठाने में हुई देरी के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि न्यायालयों को दिखाए गए कारणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-उत्साह में एक बेपरवाह(स्लिपशोड) आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर देना चाहिए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की इच्छा को डिफ़ॉल्ट पक्ष पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे नियमित तरीके से देरी को माफ करके हल्के ढंग से पराजित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मामले के पांडित्यपूर्ण और अतितकनीकी दृष्टिकोण को लेने से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में तथ्यों और कानून के उच्च और तर्कसंगत बिंदु शामिल होते हैं, जिससे उस पार्टी को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति होती है जिसके खिलाफ लिस समाप्त हो जाता है, या तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसी पार्टी के मूल्यवान अधिकार को हराना। मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो वह किसी भी तरह से पक्षों को पारित करने जा रहा है।"

10.यह ऊपर उल्लिखित निर्णयों से स्पष्ट है,

जिसमें, अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' से निपटा गया

है, जिसका अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या

किसी मामले के तथ्य और परिस्थितियां या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर कार्रवाई नहीं की है" या "निष्क्रिय बनी हुई है"।

11.यह न्यायालय, पूर्वोक्त प्रस्ताव और 110 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए देरी माफी आवेदन में प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यह जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

12. जैसा कि प्रस्तुत स्पष्टीकरण से प्रकट होता है, जिसमें, यह कहा गया है कि दिनांक 27.07.2022 के आदेश के सिविल रिट याचिका संख्या 5616/2021 में पारित होने के बाद, फाइल अनुभाग अधिकारी द्वारा शहरी विकास और आवास विभाग, झारखंड सरकार के अवर सचिव के समक्ष 22.08.2022 को रखी गई थी।

इसके बाद, फाइल को 07.09.2022 को अतिरिक्त सचिव के

समक्ष रखा गया ताकि फाइल को एल.पी.ए. दाखिल करने के निर्देश के लिए विभाग के सचिव के समक्ष रखा जा सके और विद्वान महाधिवक्ता से राय भी ली जा सके।

इसके बाद अपर सचिव ने यह फाइल शहरी विकास एवं आवास विभाग सरकार के सचिव के समक्ष रखी

सिविल रिट याचिका संख्या 5616/2021 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 के खिलाफ एलपीए दायर करने के लिए कानून विभाग, झारखंड सरकार की राय लेने के लिए 08.09.2022 को झारखंड सरकार द्वारा एक आदेश जारी किया गया था।

इसके बाद, एलपीए दाखिल करने के लिए राय लेने के लिए फाइल को 09.09.2022 को झारखंड सरकार के कानून और न्याय विभाग के समक्ष रखा गया था।

इसके बाद दिनांक 27.07.2022 के आदेश के विरुद्ध एल.पी.ए दाखिल करने के लिए विद्वान महाधिवक्ता की राय के बाद, आधार तैयार करने के लिए फाइल 20.09.2022 को विद्वान एएजी-II के कार्यालय में भेजी गई और एलपीए तैयार करने के लिए कुछ और दस्तावेजों की आवश्यकता थी और इस बीच, दुर्गा पूजा की छुट्टियां शुरू हुईं और विभाग भी बंद हो गया, इसके बाद, विभाग द्वारा एएजी-II के कार्यालय को दस्तावेज प्रदान किए गए, उसके बाद, अपील का ज्ञापन तैयार किया गया और दायर किया गया।

13. विलंब माफी आवेदन में बताए गए आधारों

से ऐसा प्रतीत होता है कि फाइल को एक विभाग से दूसरे विभाग में ले जाने का कारण दिखाने की कोशिश की गई है।

14.इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य- अपीलकर्ताके आचरण के बारे में ऊपर दिए गए संदर्भ के अनुसार-

, इसे 110 दिनों की देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है।

15. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 11.09.2023 को एल.पी.ए संख्या 430/2022 में एक आदेश पारित किया है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा दायर देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया गया है क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 128 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

16. एक अन्य मामले का संदर्भ यहां के एल.पी.ए संख्या 835/2019 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश का संदर्भ देने की आवश्यकता है, जिसमें 568

दिनों की देरी को माफ करने का मुद्दा विचाराधीन था।

इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके फाइल को एक तालिका से दूसरी तालिका में ले जाने के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

17. राज्य अपीलकर्ता ने एस.एल.पी संख्या 7755/2022 होने के नाते एस.एल.पी दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और एल.पी.ए संख्या 835/2019 में पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन एस.एल.पी संख्या 7755/2022 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 13.05.2022 के आदेश से प्रकट होगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य द्वारा 28 अप्रैल, 2023 को दायर अपील (सी) संख्या 8378-8379/2023 की एक विशेष अनुमति को भी खारिज कर दिया है, जो इस न्यायालय द्वारा एल.पी.ए संख्या 99/2021 में पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील

दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

18. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी (सी) डायरी सं (एस) संख्या 3188/2024 को दिनांक 02.02.024 को खारिच कर दिया जो झारखंड राज्य द्वारा एल. पी. ए. संख्या 401/2022 में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 14.08.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गयी थी, जिसमें 259 दिनों की बिलम्ब को माफ नहीं किया गया था।

19. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा उपरोक्त संदर्भित निर्णयों में दिए गए अनुपात पर विचार करते हुए तथा देरी माफ़ी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए इस नतीजे पर पहुचता है कि अपील दायर करने के लिए 110 दिनों की असाधारण देरी को माफ़ करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखया गया है।

20. तदनुसार, देरी माफ़ी आवेदन जो अंतरवर्ती आवेदन संख्या 10971/2022 है,को एतद द्वारा

खारिच किया जाता है।

21. इसके परिणामस्वरूप, तत्काल अपील भी खारिज हो जाती है।

22. अपील खारिज होने के परिणामस्वरूप, लंबित अंतरवर्ती आवेदन भी खारिज कर दिए जाते हैं।

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

सौरभ/**ए.एफ.आर.**

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।